



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1108]

No. 1108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2009/आषाढ़ 26, 1931  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2009/ASADHA 26, 1931

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009

का.आ. 1759(अ).—चूंकि वेस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन (महाराष्ट्र) प्रा. लिमिटेड, अनुज्ञप्तिधारी, जिसका निगमित कार्यालय द्वितीय तल, बी-विंग, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है और जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति रखते हुए विद्युत के अंतर्राज्यीय पारेषण हेतु अनुज्ञप्तिधारी है, ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है;

और चूंकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 19-3-2009 को, पत्र सं. 12-3-2009-पीजी के द्वारा विभिन्न गाँवों की कृषि भूमियों से गुजरने वाली, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, रेलवे लाइनों, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर से निकलने वाली लगभग 1035.8 कि.मी. की निम्नलिखित अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों, नामतः :-

1. पारली न्यू (पीजी)-पुणे न्यू (पीजी) 400 के.वी. डी/सी लाइन
2. पुणे (पीजी)-औरंगाबाद (एमएसटीसीएल) 400 के.वी. डी/सी लाइन
3. पारली न्यू (पीजी)-शोलापुर (लिम्बी चिचौली) (पीजी) 400 के.वी. डी/सी लाइन
4. शोलापुर (लिम्बी चिचौली) (पीजी)- कोल्हापुर (एमएसटीसीएल) 400 के.वी. डी/सी लाइन

2630 GU/2009

5. पुणे (पीजी) में लोनीखण्ड-कालवा 400 के.वी. डी/सी लाइन का एलआईएलओ

6. शोलापुर (लिम्बी चिचौली) न्यू (पीजी) में शोलापुर (एमएसटीसीएल)-कराड 400 के.वी. डी/सी लाइन का एलआईएलओ।

के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन प्रदान किया था।

और चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियाँ उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु, तार लाइनें और खंबे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं।

अतः, अब, पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत विद्युत की अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए वो सभी शक्तियाँ, निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करता है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए या अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु, तार लाइनें एवं खंबे लगाने के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं—

(i) अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है;

(ii) अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व, संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय

(1)

राजमार्ग, राज्य राजमार्गों आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी;

(iii) अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण, ओ. एण्ड एम., खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का अनुपालन करना होगा;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी को लगभग 1035.8 कि.मी. लंबी पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-II (डब्ल्यूआरएस-एसएस-II)-परियोजना बी के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है (i) लगभग 322.7 कि.मी. की लम्बाई वाली पारली न्यू (पीजी)-पुणे न्यू (पीजी) 400 के.वी. डी/सी लाईन (ii) लगभग 236.3 कि.मी. की लम्बाई वाली पुणे (पीजी)-औरंगाबाद (एमएसटीसीएल) 400 के.वी. डी/सी लाईन (iii) लगभग 135.1 कि.मी. की लम्बाई वाली पारली न्यू (पीजी)-शोलापुर (लिम्बी चिंचोली) से 400 के.वी. डी/सी लाईन (iv) लगभग 218.7 कि.मी. की लम्बाई वाली शोलापुर (लिम्बी चिंचोली) (पीजी)-कोल्हापुर (एमएसटीसीएल) से 400 के.वी. डी/सी लाईन (v) पुणे (पीजी) में लगभग 17.4 कि.मी. की लम्बाई वाली लाईन के लोनीखण्ड-कालवा के एलआईएलओ के लिए 400 के.वी. डी/सी लाईन तथा (vi) शोलापुर (लिम्बी चिंचोली) (पीजी) में लगभग 105.6 कि.मी. लम्बाई वाली शोलापुर-कराड लाईन के एलआईएलओ के लिए 400 के.वी. डी/सी लाईन (vii) इस लाईन का ब्यौरा 28 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है;

(v) अनुज्ञप्तिधारी संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाईनों का प्रचालन करेगा;

(vi) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्यक्षीन है।

[फा. सं. 11/3/2009-पी.जी.]

लोकेश चन्द्र, निदेशक

### MINISTRY OF POWER ORDER

New Delhi, the 16th July, 2009

S.O. 1759(E).—Whereas Western Region Transmission (Maharashtra) Pvt. Ltd., the licensee, with its corporate office at 2nd Floor, B-Wing, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 being a licensee for Inter-State transmission of electricity having a license under the Electricity Act, 2003 for the States of Maharashtra and Karnataka; has applied for approval of the Government of India, Ministry of Power;

And whereas on 19-3-2009, vide letter No. 12-3-2009-PG, the Government of India, Ministry of Power, had granted to the Licensee approval under Section 68 of the Electricity

Act, 2003 for the following Inter-State Transmission Lines, namely :—

1. Parli New (PG)-Pune New (PG) 400 kV D/C line
2. Pune (PG)-Aurangabad (MSTCL) 400 kV D/C line
3. Parli New (PG)-Solapur (Limbi Chincholi) (PG) 400 kV D/C line
4. Solapur (Limbi Chincholi) (PG)-Kolhapur (MSTCL) 400 kV D/C line
5. LILO of Lonikhand-Kalwa 400 kV D/C line at Pune (PG)
6. LILO of Solapur (MSTCL)-Karad 400 kV D/C line at Solapur (Limbi Chincholi) New (PG)

of approximately 1035.8 km passing through agriculture lands of various villages, crossing over the National and State Highways, Railway Lines, Local Authority Area etc.;

And whereas the licensee has now requested to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained;

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the Licensee which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned inter-state transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :—

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Licensee shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) Licensee shall have to follow regulations/codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc.;
- (iv) the Licensee has been entrusted with the responsibility of constructing the Western Region System Strengthening Scheme-II (WRSSS-II)-Project B of length around 1035.8 kms, (i) 400 kV D/C line from Parli New (PG)-Pune New (PG) having approximate line length of 322.7 km (ii) 400 kV D/C line from Pune (PG)-Aurangabad (MSTCL) having approximate line length of 236.3 km (iii) 400 kV D/C line from Parli New (PG)-Solapur (Limbi Chincholi) having approximate line length 135.1 km (IV) 400 kV D/C line from Solapur (Limbi Chincholi) (PG)-Kolhapur (MSTCL) having approximate line length 218.7 km (v) 400 kV D/C

line for LILO of Lonikhand-Kalwa at Pune (PG) having approximate line length of 17.4 km and (vi) 400 kV D/C line for LILO of Solapur-Karad line at Solapur (Limbi Chincholi) (PG) approximate line length of 105.6 (vii) the details of the line are published in the Gazette of India, 28th March, 2009;

- (v) the Licensee shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Licensee to the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F. No. 11/3/2009-PG]

LOKESH CHANDRA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2009

का.आ. 1760(अ).—चूँकि वेस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन (गुजरात) प्रा. लिमिटेड, अनुज्ञप्तिधारी, जिसका निगमित कार्यालय द्वितीय तल, बी-विंग, बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में है और जो गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति रखते हुए विद्युत के अंतर्राज्यीय पारोषण हेतु अनुज्ञप्तिधारी है, ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया है;

और चूँकि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 19-3-2009 को, पत्र सं. 12-3-2009-पीजी के द्वारा विभिन्न गांवों की कृषि भूमियों से गुजरने वाली, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, रेलवे लाइनों, स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र आदि के ऊपर से निकलने वाली लगभग 483.7 कि.मी. की निम्नलिखित अंतर्राज्यीय पारोषण लाइनों, नामतः :-

1. राजगढ़ (पीजी)-कर्मसद (जीयूवीएनएल) 400 के.वी. डी/सी
2. लिम्बडी (चोरनिया) (जीयूवीएनएल)-रणछोड़पुरा (वदावी) (जीयूवीएनएल) 400 के.वी. डी/सी लाइन
3. रणछोड़पुरा (वदावी)(जीयूवीएनएल)-जेरदा (कनसारी) (जीयूवीएनएल) 400 के.वी. डी/सी लाइन

के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी को अनुमोदन प्रदान किया था।

और चूँकि अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत सभी शक्तियाँ उसे सौंपे जाने का अनुरोध किया है, जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए अथवा इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु, तार लाइनें और खम्बे लगाने के संबंध में, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं।

अतः, अब, पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के

अंतर्गत विद्युत की अंतर्राज्यीय पारोषण लाइनों की स्थापना के लिए वो सभी शक्तियाँ, निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान करता है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए या अनुरक्षित किए गए या इस प्रकार स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु, तार लाइनें एवं खम्बे लगाने के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत तार प्राधिकरण के पास हैं—

- (i) अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है;
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व, संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी;
- (iii) अनुज्ञप्तिधारी को पारोषण, ओ. एण्ड एम., खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/कोडों का अनुपालन करना होगा;
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी को लगभग 483.7 कि.मी. लंबी पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढीकरण योजना-II (डब्ल्यूआरएसएसएस-II)-परियोजना सी के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है (i) लगभग 235.6 कि.मी. की लम्बाई वाली राजगढ़ (पीजी)-से कर्मसद (जीयूवीएनएल) 400 के.वी. डी/सी लाइन (ii) लगभग 103.7 कि.मी. की लम्बाई वाली लिम्बडी (चोरनिया)(जीईटीसीओ) से रणछोड़पुरा (वदावी) (जीईटीसीओ) तक 400 के.वी. डी/सी लाइन (iii) लगभग 144.4 कि.मी. की लम्बाई वाली रणछोड़पुरा (वदावी)(जीईटीसीओ) से जेरदा (कनसारी) (जीईटीसीओ) तक 400 के.वी. डी/सी लाइन (iv) लाइन का ब्यौरा 28 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है;
- (v) अनुज्ञप्तिधारी संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा;
- (vi) यह अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।

[फा. सं. 11/3/2009-पी जी]

लोकेश चन्द्र, निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 16th July, 2009

S.O. 1760(E).—Whereas Western Region Transmission (Gujarat) Pvt. Ltd., the licensee, with its Corporate Office at 2nd Floor, B-Wing, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 being a licensee for Inter-state transmission of electricity having a license under the Electricity Act, 2003 for the States of Gujarat and Madhya Pradesh; has applied for approval of the Government of India, Ministry of Power;

And whereas on 19-3-2009, *vide* letter No. 12-3-2009-PG, the Government of India, Ministry of Power, had granted to the Licensee approval under Section 68 of the Electricity Act, 2003 for the following Inter-State Transmission Lines, namely :—

1. Rajgarh (PG)—Karamsad (GUVNL) 400 kV D/C line
2. Limbdi (Chorania) (GUVNL)—Ranchodpura (Vadavi) (GUVNL) 400 kV D/C line
3. Ranchodpura (Vadavi) (GUVNL)—Zerda (Kansari) (GUVNL) 400 kV D/C line

of approximately 483.7 km passing through agriculture lands of various villages, crossing over the National and State Highways, Railway Lines, Local Authority Area etc.

And whereas the licensee has now requested to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained.

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the Licensee which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely :—

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Licensee shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the licensee shall have to follow regulations/ codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc.;
- (iv) the Licensee has been entrusted with the responsibility of constructing the Western Region System Strengthening Scheme-II (WRSSS-II)—Project C of length around 483.7 kms, (i) 400 kV D/C line from Rajgarh (PG)—to Karamsad (GUVNL) having approximate line length of 235.6 km (ii) 400 kV D/C line from Limbdi (Chorania) (GETCO) to Ranchodpura (Vadavi) (GETCO) having approximate line length of 103.7 km (iii) 400 kV D/C line from Ranchodpura (Vadavi) (GETCO) to Zerda (Kansari) (GETCO) having approximate line length of 144.4 km (iv) the details of the line are published in the Gazette of India of 28th March, 2009;
- (v) the Licensee shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Licensee to the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F. No. 11/3/2009-PG]

LOKESH CHANDRA, Director